[Shri A. G. Kulkarni]

give you on loan, but please return these to me. These are the documents. Please see them. Reliance Industries have defrauded this Government, particularly this Reliance industry, of Rs. 600 crores. You give this money to Shri Bhajan Lal and he will energise 10 lakh pumps with that amount. Two hundred crores of rupees in customs duty evasion. Who will pay for that? We poor people toil and you have got this marathon run or whatever it is, for the country, etc. This is Yuppie culture. Don't run. We are fretting in the crowd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH RESAI): Now, nothing more. (*Interruptions*).

SHRI A. G. KULKARNI: So, Mr. Vice-Chairman, this type of culture we are not going to bring into this country. Our culture is what Mahatma Gandhi and Nehru stated, and that culture we nurse and for that purpose we want your help. Break the nexus of black money with the administration, the bureaucracy and the politician.

STATEMENT BY MINISTER

Price Policy for raw jute and raw cotton for the 1989-90 season

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : महोदय, सरकार ने 1989–90 मौसम के कच्चे पटसन कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया है।

कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने के लिए आसाम में मूलभूत किस्म डब्ल्यू–5 से परिवर्तित करके टी० डी–5 कर दी गई है जो कि ओलिटोरियस पटसन को शीघ्र बुवाई व्यापक रूप से अपनाए जाने के कारण हुआ है।

1989–90 मौसम के लिए आसाम में कच्चे पटसन को मूलभूत किस्म यानि टी. डी.–5 ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 280 रु. प्रति क्विंटल तय किया गया है जो कि पिछले मौसम के समर्थन मूल्य से 17.50 रु. प्रति क्विंटल अधिक है।

कच्चे पटसन को टी. डी–5 और डब्ल्यू 5 किस्मों का परस्पर मूल्य अन्तर, जो कि पिछले वर्ष 12.50 रु. प्रति क्विंटल था, बढाकर 15 रु. क्विंटल करने का भी निर्णय लिया गया है।

अन्य श्रेणी के केप्सूलरोज और ओलिटोरियस पटसन के संगत मूल्य पटसन आयुक्त द्वारा सामान्य बाजार भाव अन्तर को देखते हुए नियत किए जाएंगे। परिणामस्वरूप 1989–90 मौसम के लिए आसाम में डब्ल्यू–5 ग्रेड का यह न्यूनतम समर्थन मूल्य 265रु० प्रति क्विंटल बनेगा जो कि 1988–89 मौसम में 250 रु. प्रति क्विंटल था।

यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिरती हों तो भारतीय पटसन निगम समर्थन कार्य यथापूर्व अपने हाथ में लेगा। यह भी तय किया गया है कि कच्चे पटसन के अपने स्टाक निकालने के बारे में भारतीय पटसन निगम सावधानी पूर्वक विचार करेगा ताकि संभावित मूल्य वृद्धि को सामान्य आकस्मिक स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

अच्छी औसत किस्म एच–4 किस्म को लम्बे और बढ़िया लम्बे रेशे वाली 1989–90 मौसम की कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रु. प्रति क्विंटल होगा जो कि 1988–89 के मौसम के लिए नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। एफ–414/एच–777 किस्म वाली बढ़िया औसत किस्म की कच्ची कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 540 रु. प्रति क्विंटल होगा। यह मूल्य गत मौसम की इस अवधि के मूल्य से 40 रु प्रति क्विंटल अधिक है। एच–4 तथा एफ–414/एच 777 को छोडकर अन्य किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य मूल्य अन्तर के आधार पर कपड़ा आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

यदि कच्चे कपास के बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के स्तर से नीचे गिरने शुरू हो जाएं तो भारतीय कपास निगम मूल्य समर्थन कार्यों को अपने हाथ में लेगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में यह वृद्धि देने से किसानों को कपास और कपास का उत्पादन और उपज और अधिक बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all I thank the honourable Minister for giving minimum support price for jute and cotton. Sir, in our country, cotton production is about 96 lakh bales and the consumption is about 102 lakh bales. Now we are short of cotton supplies in this country. In the previous years, till 1987, we were exporting cotton. In 1988-89 we have had a little import. We have completely stopped export of cotton from this country. Sir, the support price which the hon. Minister has announced for cotton, is Rs. 50 for long-staple cotton and that for average-staple cotton is Rs. 40 That is the price the hon. Minister has given. Sir, this price has been announced to keep the price line under control. Sir, the farmers who are growing cotton, are from Maharashtra, Andhra Pradesh and Gujarat. The major cotton production comes from those States.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Punjab also.

SHRI BHAJAN LAL: Punjab and Haryana also,

SHRI V. NARAYANASAMY: Punjab and Haryana also. The major cotton-growing centres, I mentioned.

Sir, in this respect, I would like to tell the hon. Minister, they allowed to have a minimum support price for cotton. But, as far as jute is concerned, they have a statutory minimum support-price. As per the law, if jute is sold below the Minimum support price, the person will be prosecuted. But, as far as cotton is concerned, that restriction is not there. I would like to know from the hon. Minister why there is such a discrimination between these raw materials.

Sir, for cotton which is being produced by our farmers, the technology has not developed and improved. The long-staple cotton which is being produced in various parts of the country, does not meet our requirement though we are cultivating cotton in a larger area. Sir, we came to know several cases of farmers dying due to wrong application of fertilizers. In Andhra Pradesh in the Prakasam District, we know, several family members have committed suicide when their crops failed.

Sir, another important thing which I have raised several times in this House as far as cotton is concerned, is, inventions are being made for the purpose of improving the varieties, quality and quantity of cotton crop, but that particular invention has not gone to the farmers so far. It is quite surprising.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Be pointed now. There are many Members who will speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am pointing out important aspects only. This is a vital thing. Several crores of rupees have been spent on science and technology, especially for developing imporved varieties of cotton in univerisities and also in agricultural centres. But those inventions have not gone to the farmers as such. I would like to know from the hon. Minister what mechanism they are going to adopt to see that the price-line does not go below the minimum support-price which has been announced by the Government. The middlemen are thriving. My submission is, if cotton goes to the market, co-operative market, it is all right. Now middlemen are engaged in these cotton sales. The Cotton Corporation

[Shri V. Narayanasamy]

of India is also there for the purpose of distribution and to hold the stock to avoid a crisis. To avoid the middlemen...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): They have to buy. If it is below the minimum price they have to buy.

SHRI V. NARAYANASAMY: They have to buy. They have to keep the price line under control. The middlemen are very much engaged as far as cotton is concerned. That is to my knowledge. The private persons who are engaged in this business, leaving alone societies which are in this country, are thriving. The farmer is poorly paid. The middlemen are getting much money. The textile trade gets a higer amount. Therefore, to eliminate the middlemen, what steps is the Government going to take?

As far as jute is concerned—he is interested in jute—the main States which are affected are West Bengal and Assam. Sir, the Government brought strict guidelines requiring the public sector units to make use of the gunny bags if they come under industry. But the Minister of Agriculture must also be concerned with that. They have to make use of jute bags for the purpose of holding the stocks. They have been defying the orders. The Minister of Agriculture is also concerned with that. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what steps he is giving to take. I am very happy that the support price has been announced, and I would like to know, for stricter implementation of that particular provision what steps the Agriculture Ministry is going to take in this regard.

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि जूट और कच्ची कपास के दाम और सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दिये गये हैं । इससे किसानों का बहुत उत्साह बढ़ेगा और उनका लाभ होगा । उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर या कन्सट्रेटेड वे में तो कपास पैदा नहीं होती है लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लोग कुछ न कुछ मात्रा में कपास न पैदा करते हों । कपास भी अच्छी किस्म की होती है और वह दूसरे सूबों में चली जाती है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पैदा होने वाली सारी कपास यहां दिल्ली चली आती है । जैसा कि कहा गया है कि अन्य खरीददार कपास नहीं खरीदेंगे केवल सरकार खरीदेगी तो मेरी चिंता यह है कि गवर्नमेंट का एक सेंटर बनना मुश्किल है क्योंकि वहां इतने किसान बेचने वाले नहीं हो सकते हैं इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जहां पर गवर्नमेंट का एक सेंटर पूरा हो सकता है, उसके बजाये कुछ जिलों को मिलाकर जहां पब्लिक के बिजिनेस मैन खरीदकर सरकार को दे सकें, इसके लिए क्या कुछ सब सेंटर्स देने पर आप विचार करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के होल टाइम सेंटर जहां मुमकिन नहीं है वहां सब सेंटर्स बनाने का एलान करके सरकार उनको सपोर्ट प्राइस दे सकती है ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे, भजन लाल जी कृषि मंत्री हैं और एक बहुत ही कुशल मंत्री हैं । उन्होंने अभी सपोर्ट प्राइस के बारे में बयान दिया और कपास के दाम 40 रु० से 50 रुपये प्रति क्विंटल तथा जूट के 15 से 20 रुपये क्विंटल बढ़ा दिये हैं । यह किसानों के लिए काफी राहत की बात है । मैं उनका इसके लिए आभारी हूं और बधाई देना चाहता हूं । जब भजन लाल जी पहली बार कृषि मंत्री होकर आये तो हमारे किसानों की सारी जो क्राप्स थी उनके दाम बढ़ा दिये जिनकी मांग हम लोग गये 5–6 साल से इस सदन में कर रहे थे । इसलिए मैं भजन लाल जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारा जो किसान है, जो पिछड़ा हुआ है दबा हुआ है और जो उत्पादनकर्ता है, अपने खेत में पैदा करता है उसको योग्य दाम नहीं मिलता है । आपने काफी कोशिश की है.....

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : जल्दी खत्म कीजिए। बागडोदिया जी को जल्दी जाना है।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : जरा बात तो खत्म होने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : तो मैं उनको जरा पहले मौका दे दूं Can I give him the time because he is to leave?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : कोई बात नहीं उनको बुलवा दीजिए।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): I am really grateful to Jadhav Ji also for letting me to speak in between.

First I would like to compliment the hon. Minister for increasing the prices for raw jute and also for cotton.

In the case of raw jute I would like to point out that at least this year the prices are much much higher—at least 20 to 25 per cent higher—than the minimum prices. So, I really do not know if this kind of increase is really going to help in a very big way. In fact, I would suggest that the increase of Rs. 17.50 for TD-5 grade for Assam may please be increased at least by Rs. 5 or it can be increased up to Rs. 25 instead of Rs. 17.50 Similarly, the difference between the TD-5 grade and W-5 grade is of Rs. 15 only. I would like to point out to the hon. Minister that with the modern technology, the better quality jute is more in demand than the poor quality jute. So, the difference can also be increased at least by Rs. 5 more. If you do this it will be more realistic.

In the last sentence on Jute, the Minister in his Statement has said:

"...The Jute Corporation of India should carefully rationalise the releases of stocks of raw jute held by it in order to meet the exigencies of a possible rise in the prices in the lean period."

It is most unfortunate that the JCI has not done its duty properly this year. It is not releasing the stock. It should freely release the stocks. Let us understand one thing that the jute is not lying in the hands of the farmers. The entire jute is lying in the hands of the middlemen. The entire advantage is going to the middlemen. In the process the workers and the mills are suffering. So, let there not be this feeling that it is the farmer who will suffer if the JCI releases the stocks. When the prices are much much higher, there should be liberal import of jute also. When all the export industries are allowed to import their raw materials why stepmotherly treatment to the most important industry or the most traditional industry in the country? Jute is not being allowed to be imported against exports also.

On cotton, I am not going to say too much at the moment. One more thing our hon. Prime Minister had given a package deal of Rs. 250 crores in 1986 which included modernisation of jute industries, etc. etc. But out of Rs. 250 crores, Rs. 25 crores were earmarked only for development of raw jute. Though Rs. 25 crores have been sanctioned for improving the yield of raw jute and extension programme, the progress is very slow. It is imperative that jute is available to the Indian mills at approximately the same price as that available to the Bangladesh jute mills but to maintain that low price and give added return to the farmers, the yield has to go up drastically. It has been proven in pilot prospects that yeild can go up by more than 50 per cent. This could mean a substantial inducement to the farmers to produce raw jute at economical prices. One more small point on jute under the Jute Agricultural Development Programme the yield is, of course, the most important thing but the scheme is not strengthened. There should also be proper dissemination of information and publicity regarding the work be-

[Shri Santosh Bagrodia]

ing undertaken under this scheme and the benefits to the farmers. Expert teams from the industry and the Government of India should visit areas where the scheme is being implemented and see that they get on-the-spot benefit.

Sir, Rs. 10 crores have been allotted to JCI and cooperative procurement agencies. Out of Rs. 10 crores, only Rs. 7 crores in 2-1/2 years has been actually earmarked for developing the 24 godowns, at the cost of Rs. 29 lakhs per godown. I cannot understand why we cannot allocate the balance Rs. 3 crores as quickly as possible even though the godown rates have been fixed at Rs. 200 per sq. per ft. which seems to be very high.

Now, the final point. My colleague, Mr. Narayanasamy has mentioned about the statutory price. I fully support the minimum prices. But why do we need statutory prices? In the process of statutory prices what is happening in JCI is that stocks are lying for the last two years and as a result of this the quality of jute goes down. They have not been able to sell it at the minimum price. They have not been able to sell it at all because they cannot sell it less than that price. In the process the entire stocks go waste. I think in Bihar godowns about 2 lakh bales or something are going waste and nobody is going to buy at that price. Similarly, when the prices sometimes go below the minimum price what happens is that there is collusion between the traders and the mills. This is how we are encouraging the blackmarketeers and generation of black money because they have to sell it at the minimum price. They give the bill at the minimum price and the balance is returned in cash. So like cotton if we can make it a minimum price without making a statutory minimum price this will help the farmers and our purpose wil be served without generating black money.

Coming to cotton I want to compliment our hon. Minister for increasing the prices of cotton. This year we have plenty of cotton in our country but last year we had a great problem in cotton supply. Our cotton yarn and cotton goods are very popular in the world market. If the cotton production can be increased it will help us in a big way for our cotton mills to export more goods in the interest of the country. Thank you, Sir.

श्री विठ्ठलराव मधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं अभी कह रहा था कि भजन लाल जी ने कपास और जूट की प्रोक्योरमेंट प्राइसेज बढाई है, उसका मैं समर्थन करता हूं। बात ऐसी है कि हमारे किसान बहुत होशियार हैं। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह मेरे दिल में आई है कि इसे कह दूं। शहरों में बैठे हुए जो इकानोमिस्ट हैं, वह कहते हैं कि किसान कुछ समझता नहीं है। वह समझता तो सब कुछ है, मगर उसके पास अर्थ न होने की वजह से अनर्थ होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There are so many Members to seek clarifications. Please be brief.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव :*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): These remarks are very unfair and these will not go on record.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो कपास की कीमत बढ़ाई गई है, मैं जूट की तरफ तो नहीं जाता, मेरे मित्रों ने यह पूछा है कि हमारे देश में जो किसानों के लिये, महाराष्ट्र में जो काटन मोनोपली स्कीम

*Not recorded.

चलाई गई है और महाराष्ट्र ने कई बार केन्द्र को यह रिक्वेस्ट किया है कि इसकी मुद्दत दस वर्ष तक बढ़ाई जाये। काटन मोनोपली स्कीम में आप जो 640 रूपये कीमत दे रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी काटन मोनोपली स्कीम अभी किसानों को अपनी स्टेट में से कोटा ज्यादा पैसे दे रही है, इसलिये किसान खुश है। फिर भी जब कास्ट आफ प्रोडक्शन जो कपास के लिये होता है और उनको जो रिटर्न मिलता है फिर भी किसानों को योग्य दाम नहीं मिलता। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि यह जो कपास है, कपास की काटन मोनोपली स्कीम जैसे महाराष्ट्र ने बनाई अगर सारे देश में इसका अमल किया जाये, क्योंकि काटन कोआपरेटिव मूवमेंट में जब काम करते हैं, आप देखते होंगे तो कि गये बीस साल में शूगर इण्डस्ट्री 30 लाख टन से 90 लाख टन तक बढ़ी है, मगर कपास की इण्डस्ट्री को जब हम देखते हैं तो उसमें ज्यादा वृद्धि नही हुई, क्योंकि जो उत्पादक है, उसके हाथ में जब कारखाना जाता है, तो वह अच्छी तरह से काम करता है, जैसा कि महाराष्ट्र में शूगर फैक्टरी कोआपरेटिव सैक्टर में आने की वजह से शूगर का उत्पादन बढ़ा है और किसानों को दाम मिले हैं, लेकिन जब हम कपास की तरफ देखते हैं, उप-सभाध्यक्ष महोदय, आप बम्बई से आते हैं, 25-30 मिल बन्द होने पर आई हैं, क्योंकि उद्योगपति चाहता है कि उनको उससे क्या फायदा है, उस उद्योग से उनको कितना धन मिलता है, उसको कितना मुनाफा मिलता है, उसको ध्यान में रखते हुए यह कैसे चलायेंगे? मुनाफा ही इस चीज को तय कहता है। यह कपास उत्पादक किसान है, मगर उसका रॉ मैटिरियल जाता है, उद्योगपति के पास टैक्सटायल मिल्ज में, कपड़ा 15/- मीटर बेचता है। एक किलो रूई में आठ मीटर कपड़ा तैयार होता है, तो यह एक किलो रूई के लिये तीन किलो कपास होती है। अभी 640 रूपये कीमत है, इसका मतलब है कि 14 रूपये में एक किलो रूई तैयार होती है और उसका कपड़ा 120/- रूपये का हो गया। 15 रूपये का कपास और उसका 120 रूपया मिल मालिक को मिलता है। वह कामगार का शोषण करता है, प्रोफिट खा जाता है, बैंकों को फंसाता है, सरकार को फंसाता और हमारा किसान पिछड़ा हुआ होता है। इसके बारे में आप क्या करने वाले है, यह सब से बड़ा सवाल है ? जब देश में कृषि का उत्पादन बढ़ता है, तो इकोनोमिकल स्थिति अच्छी होती है। इस साल हमारी इकोनोमिक स्थिति अच्छी है क्योंकि कृषि के माल पर आधारित बहुत से उद्योग हमारे देश में चलते हैं। चाहे टैक्सटाइल मिल्ज हों, जूट मिल्ज हों, फूड प्रोसैसिंग इंड ट्रीज हों या इलेक्ट्रिक मोटर्ज हों, आयल इंजन हों उसका जो मुख्य ग्राहक है वह किसान है। जब किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी तब तक ये बाकी के कारखाने और बाकी के उद्योग अच्छी तरह से नहीं चल सकते। तो इसके लिए जैसा अभी कुलकर्णी जी ने कहा कि हर साल 8 करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र के अर्बन एरिया में रूरल एरिया से जा रहे हैं, तो यह क्यों जा रहे हैं? वह शोषण कहां हो रहा है? जैसे कि मैं जानता हूं, वैसे ही भजन लाल जी भी जानते हैं, जब हम किसानों को या कृषि उत्पादन करने वालों को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तब तक कृषि को हम उद्योग नहीं मानेंगे, तब तक इस कृषि को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि यह प्रिंसीपल तत्व इसको मान्य किया जाए कि कृषि को उद्योग समझा जाए। जैसा प्राइस इंडेक्स बढ़ता है प्राइस इंडेक्स 430... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Jadhav, this is a limited subject and you are speaking as if you are making a speech on agriculture.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, it is very much relevant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): What I say is, this is a limited subject but it appears as if you are speaking on agriculture. Please confine yourself. I cannot give this much time.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I will conclude within half a minute.

तो मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इसके बारे में बहुत समग्र विचार करने की जरूरत है और कपास देश का सब से बड़ा उद्योग है, यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब से बड़ी इंडस्ट्री है और इसके लिए भी जो प्राइवेट लोग हैं उनसे इसे निकालकर अगर कोआपरेटिव सैक्टर में जो मिल्ज हैं अगर इन्हें दे दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कपास को अच्छा बढ़ावा मिलेगा ।

दूसरी बात एक्सपोर्ट कोटा के बारे में है । अभी सुबह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि कितना एक्सपोर्ट कोटा दे रहे हैं तो 1986-87 में हमने 13 लाख बेल्ज एक्सपोर्ट की मगर इस साल एक लाख एक हजार दो सौ इक्कीस बेल्ज एक्सपोर्ट के लिए रखे हैं । अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें तो हमारी जो महाराष्ट्र की समस्या है क्योंकि एपास की बेल्ज पड़ी हुई हैं, किसानों को पैसे नहीं दे सकते, भजन लाल जी ... (व्यवधान)

श्री मोर्जा इर्शाद बेग (गुजरात) : भजन लाल जी तो चाहेंगे, लेकिन कामर्स मिनिस्टरी एलाउ नहीं करेगी ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं जानता हूं भजन लाल जी को, मैं उनको इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूं... (व्यवधान) । मुझे मालूम है कि यह कामर्स मिनिस्टरी के हाथ में है । मगर कृषि मंत्री इतने कुशल हैं कि अगर वह अपना जादू चलायें, तो वह भी मान जायेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि किसानों को न्याय दिलाने के लिये यह सब बातें की जायें । धन्यवाद ।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक मिनट लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं, आपको बाद में मौका दूंगा ।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : मान्यवर, मैं तानाबाना बनाता हूं, कपास इस्तेमाल करता हूं, कपड़ा बनाता हूं.... (व्यवधान) .... ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपको मौका दूंगा ।

I will allow you. Please, listen to me. Please, sit down. I will give you a chance. (*Interuptions*)

आपको चांस देने वाला हूं । मगर आपसे पहले जिन्होंने नाम दिया है, उनको भी बोलना है । आपको मौका देने वाला हूं, आपका नाम मैंने लिख लिया है मीर्जा इर्शाद बेग ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मानगीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पटसन और कपास के संबंध में विशेष समर्थन मूल्य घोषित करने और उसमें की गयी बढ़ोत्तरी के लिये कृषि मंत्री भजन लाल का अभिनन्दन करता हूं । उन्होंने राजीव गांधी की और कांग्रेस सरकार की नीति को फिर से एक बार स्पष्ट किया है कि वह किसानों को हर कीमत पर, हर अवस्था में सहायता प्रदान करना चाहते हैं । भजन लाल जी तो धरती के पुत्र है, इसलिये उसकी समस्या क्या हो सकती है, उनको भलीभांति मालूम है ।

महोदय, मैं दो-तीन मुद्दे इस संबंध में उठाना चाहूंगा । पटसन के संबंध में पहले भी सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है और उसके इण्डस्ट्रीज के उपयोग के बारे में भी ताकि पटसन उगाने वाला जो किसान है, उसको लाभ पहुंच सके और इसलिये उन्होंने जूट बेग का जो प्रतिशत निर्धारित किया है, इण्डस्ट्री के उपयोग के लिये, मैं समझता कि उसका परसेंटेज रेशो जो है, वह मेण्टेन करें, तो हम किसानों को, पटसन उगाने वालों को, सही मात्रा में सहायता प्रदान कर पायेंगे ।

मान्यवर, एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद एक पास उत्पादक हूं और हमारा आधार यही है, वर्षों से कपास का

उत्पादन हम लोग करते हैं। मान्यवर, मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात के उस इलाके से संबंध रखता हूं, उत्तर गुजरात से, जहां हम लोग कपास की जो वैरायटी पैदा करते हैं, संकर-चार, यह लोंग स्टेपल, देश की सबसे अच्छी वेरायटी में से एक है। मैं समझता हूं कि इसका विदेश की मार्किट में भी बहुत अच्छा दाम मिलता है। मान्यवर, आज भजन लाल जी को बहुत स्पष्ट तौर से यह कहना चाहूंगा, वह इस बात को गौर से सुनें और आगे तक पहुंचायें। किसानों के साथ अन्याय कब होता है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उत्तर गुजरात का दृष्टांत मैं आपके सामने रखूं तो उत्तर गुजरात में हर वक्त चार साल का सूखा हुआ। उपाध्यक्ष जी, आप मुझे समर्थन देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, इसलिये मुझे माफ करेंगे, अगर मैं थोड़ा समय लूं, तो .... (**व्यवधान**) ...।

उपसभाध्यक्ष जी, always you are fair enough to us. हमेशा आपने हमें समय दिया है, आज भी देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

मान्यवर, अगर साइंटिस्टों के सर्वेक्षण भी आप देखें, तो किसानों के लिये खेती पूरी वर्षा पर आधारित होती है और हमारे यहां एरोगेशन को फेसलिटीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तीन साल में एक ही वक्त ऐसा आता है, जिसमें किसान को कुछ मिल पाता है। तीन साल ऐसे ही कोरे जाते हैं। अगर आप बैंकों के आकड़ों को देखें या दूसरे सर्वेक्षणों को देख, तो पता चलेगा, उसकी क्या हालत है।

मान्यवर, चार साल से गुजरात में सूखा था, विशेषकर उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्से तो विशेष रूप से एफेक्टेड थे। चार साल के बाद यह वर्ष ऐसा था कि हम आशा में थे, वह वर्ष आ गया, हमारे दो सीजन चले गये। अब यह पहला वर्ष था, चार वर्ष के बाद और हम इतने खुश थे, मान्यवर, मैं अपने फार्म पर भी गया, अपनी कपास देखने, तो इतनी सुन्दर कपास की फसल लहलहाती थी, लेकिन इसमें कहीं से व्हाइट फ्लाई नामक कीटाणु ने आक्रमण किया, यह गुजरात में भी हुआ, आन्ध्र प्रदेश में भी हुआ, सरकार ने खैर कुछ कदम भी लिये, लेकिन इससे परिस्थिति क्या हुई? किसान पर इसका दूरगामी असर क्या पड़ता है? वह मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। इसके लिये मैं चाहूंगा कि एक विशेष नीति निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि ऐसी परिस्थिति बार-बार नहीं आती है। भाव डाउन होते हैं, भाव ऊपर उठते हैं। यह एक तालमेल वाली परिस्थिति है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति जब आती है, तब आप उत्तरी गुजरात का उदाहरण लेकर देखिए, प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जबकि वहां सब से अच्छी क्राप होने की संभावना थी, तब 65-70 प्रतिशत कपास का उत्पादन इस व्हाइट फ्लाइज से घट गया। मान्यवर, गुजरात राज्य के कृषि विभाग ने कहा है कि वहां 15 लाख गांठों से अधिक का उत्पादन नहीं होगा। इस वर्ष जहां कि 10 करोड़ के कपास उत्पादन की अपेक्षा की गयी थी, सिर्फ 4 करोड़ का उत्पादन हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मीर्जा जी, जरा जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग: महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महोदय, उत्तरी गुजरात में जीनिंग की 30 फैक्ट्रीज हैं। इसमें से 12 सहकारी तथा अन्य निजी क्षेत्र में हैं। ये अपनी क्षमता का 50 प्रतिशत काम कर रही हैं। सौराष्ट्र कच्छ के इदय क्षेत्र की सबसे बड़ी जीनिंग फैक्टरी जो सीजन में 35 हजार गांठ का काम करती थी, इस वर्ष सिर्फ 5 हजार गांठ का काम किया है और खरीददारी के हिसाब से आज भी उसके पास 2 हजार गांठ बिना बिक्री पड़ी हुई हैं। मान्यवर, मिल क्षेत्र के लोग भी किसान की इस असहाय स्थिति का सम्पूर्ण फायदा उठाते हैं। दो गांठें यानी एक खांडी के दो महीने पूर्व जहां 10 रुपये थे, आज उसकी कीमत सिर्फ 7

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

हजार 5 सौ रुपये हो गयी है। जहां किसान को बीस किलोग्राम के 200 रुपये मिलते थे, आज उसे सिर्फ 140 रुपये मिलते है। किसान का क्रम प्रतिवर्ष इसी तरह चलता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तरी गुजरात के इन कपास उत्पादक किसानों की सहायता करें और ऐसी नैसर्गिक आपदाओं में क्षतिपूर्ति के साधन जुटाने की दिशा में कोई नीति निर्धारित करें। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार को इस संबंध में एक विशेष अनुदान दिया जाये और जो सपोर्ट प्राइस है, उसमें 20 प्रतिशत अधिक इन किसानों को उपलब्ध करायें। मैं मंत्री जी से क्लैरीफीकेशन चाहूंगा कि क्या वे इस विषय पर सोचेंगे। इसी तरह से जहां पर कि ब्लाइट फ्लाइज जैसी विपत्ति आती है, उसको रोकने के लिये प्रवेंटिव मेजर्स अपनायेंगे, जिसके बारे में माननीय श्री जाधव जी ने भी कहा है। मान्यवर, यह तो एक विष चक्र है कि किसान और टैक्सटाइल कभी एक साथ प्रसन्न नहीं रह सकती हैं। यह नीति और संकलन की दोषपूर्ण स्थिति है, जिसके कि वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस बारे में वे वैज्ञानिक विश्लेषण करवायेंगे, क्योंकि वस्त्र उत्पादक, टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज, उपभोक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार इन चारों तत्वों को ध्यान में रखकर एक आमूल परिवर्तन कर कोई नीति निर्धारित नहीं की जायेगी, मैं समझता हूं कि यह विष चक्र चलता रहेगा। मान्यवर, अभी जाधव जी ने कहा कि खरीददारी में आये हैं, लेकिन खरीददारी में कब आये हैं। एक्सपोर्ट करने की बात हम कब करते हैं, जब किसान का माल प्राइवेट लोगों के गोदामों में चला जाता है, तभी हम नीति घोषित करते हैं, 10 बेल या 25 लाख बेल हम एक्सपोर्ट करेंगे। उस वक्त उसका मुनाफा बिचौलियों के पास जाता है और किसान रोता हुआ बैठता है। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या इस बारे में कोई दीर्घकालीन नीति पर वे विचार करेंगे और विचार कर फायनेंस मिनिस्ट्री और खासतौर पर कामर्स मिनिस्ट्री को कहेंगे? मैं आशा करता हूं कि भजन लाल जी एक किसान की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिये वे इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर वे कोई निर्णय जरूर लेंगे। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपकी कपास की जो क्राप होती है, उसका जो एस्टीमेट आफ काटन क्राप है। I want the estimate of cotton crop. During the last five or six years it has gone down and that is why the export has not been to the extent it should have been. You kindly examine it.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: We appreciate you. We congratulate you because the Chair is associating.

SHRI MIRZA IRSHADBAIG: We thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : आपसे जो तो सभी संबद्ध हो जायेंगे, उपसभाध्यक्ष महोदय।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और कृषि मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जूट और कपास के कुछ न्यूनतम लागत मूल्य बढ़ायें हैं। जो बड़े रेशे का कपास है, उसका 650 किया 600 से और 540 किया है, दूसरे कपास का और बीच में उन्होंने किया है, 250 रूपये से 265 रूपये। जो मूल्य वृद्धि की है न्यूनतम, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं कृषि मंत्री जी से 2–3 सवाल करना चाहता हूं। एक तो हमारा जो लागत मूल्य आयोग बना

है, उसकी सिफारिशों क्या थीं, जूट और कपास के बारे में।

दूसरे आपने कहा कि जूट निगम फिर तय करेगा अगर संतोषजनक कीमत जूट की नहीं होगी तो। तो जूट निगम और केन्द्र सरकार में क्या सामंजस्य है? उसको आदेश दे सकते हैं या उसके रहमोकरम पर रहेगा और जो लागत आती है, उसके मुताबिक मैं इसको कम जानता हूं कि कम है, इसको बढ़ाने में जूट निगम या आप मिलकर कुछ और कर सकेंगे? जो बढ़ाया उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि लागत मूल्य क्या है, इसके सही आंकड़े बनाने की अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। असलियत यह है कि उनके बीच में बैठकर के अगर हम उनको लागत साल भर की या 6 महीने की लगायें, तो उनको कम दाम दिया जा रहा है। इसी तरह से मैं कपास के बारे में भी जानना चाहता हूं कि कपास के बारे में भी लागत मूल्य आयोग की गुजाइश आयोग की सिफारिश आई थीं? आपने जो दिया है, उसके लिये तो धन्यवाद, लेकिन क्या और इसे बढ़ाने की गुजाइश है या नहीं? इसी तरह से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कपास की खेती दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, हमारे कपास के फील्ड खाली पड़े हैं। जमीन में ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा कोई शोध करना चाहेंगे, आप कि मिट्टी में क्या खराबी आई है? उन इलाकों में जहां प्रायः कपास होती रही है, दुबारा रिसर्च करा कर कपास की खेती की पैदावार कराने के लिये, आप कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले साल एक कपास की रिसर्च करने वाले डाक्टर का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में जो कपास की जमीन फट गयी, कपास सारी सूख गयी और उसका गूलर गिर गया, ऐसी एक रिसर्च रिपोर्ट नकली थी समाचार पत्रों में। उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कांफी इन्दौर के आसपास का इलाका था। तो यह जो कपास पर आपत्ति है, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गई, बहुत से हिस्सों से गई, हरियाणा से भी गई—हिसार में तो जरूर होती है कपास, आपके और जिलों से भी चली गई और गुजरात के काफी हिस्सों में अभी है। मैं जानता हूं कि जहां-जहां कपास है। तो ऐसा कोई शोध आप कराना चाहते हैं कि कपास की क्यों दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं और जो बुनियादी सवाल भी है, चाहे वह कपास पर लगाए, चाहे जूट पर लगाए या किसान की और पैदावार पर। आज यह कटु सत्य है कि जगह बदलने वाला व्यापारी और शक्ल बदलने वाला उद्योगपति कई गुना मुनाफा किसान की पैदावार का कमाता है। इसको कैसे कम किया जाए? क्या कोआपरेटिव सोसायटी किसानों की बनाकर के ऐसे छोटे उद्योग जो खेती पर ही आधारित हों, सिर्फ उन्हीं इलाकों में जहां जिस चीज की पैदावार अधिक है, उन्हीं में खेती पर जो उद्योग बन रहे हैं उन्हीं के आधार पर या सरकारी आधार पर उद्योग खुलवाने को कोई योजना है या नहीं, कि किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिल सके? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

मैं यह जरूर कहूंगा कि आज बढ़ते हुए उद्योगों का प्रदूषण, शहरों के नजदीक-नजदीक और उपजाऊ जमीन को आए दिन उद्योग और आबादी के लिए ग्रहण किया जाना, जो देश की भावी योजना के लिए बड़ा खतरा है, क्या वहीं पर छोटे-छोटे कृषि आधारित उद्योग लगाकर, शहरों में जहां बोझ भी बढ़ रहा है और क्राइम भी बढ़ रहे हैं, इस बोझ को कम करने के लिए इस तरह की आपकी कृषि आधारित उद्योग, कोआपरेटिव बेसिस पर, गवर्नमेंट के बेसिस पर, राज्य सरकारों के बेसिस पर लगाने की, क्या आपकी कोई ऐसी योजना है या नहीं?

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : खाली मुकाम उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपका जब नम्बर आया तब आपको बुलाया ।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं । मान्यवर, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर करूं, में एक शेर कह देना चाहता हूं :

हम ही चिराग की लौ हैं, हम ही हैं परवाने,

यह और बात है महफिल हमें न पहचाने ।

श्री मोर्जा इशाबेग : हम ही हम है तो क्या कम हैं ?....(व्यवधान)

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : मान्यवर, 80 करोड इंसान का तन ढाकता है पावरलूम और हैंडलूम और किसान भी उसमें शामिल है । जिस तरह से कपास का रेट मंत्री जी ने फिक्स किया है इस से पहले जो गोदामों में सेठ, साहूकार कपास, जखीरा कर लिए हैं, अगर वे सेठ, साहूकार दलाल इस उम्मीद में है कि हम सरकार पर दबाव डालकर कपास ऐक्सपोर्ट करेंगे तो इशेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के तहत मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करें । उनके जखीरे पर छापा मारें, कपास को बाहर निकालें, सूत को सस्ता करें ताकि लोगों को सस्ता कपड़ा मिले ।

मान्यवर, मंत्री जी को कपास का बड़ा ख्याल है, किसानों का बड़ा ख्याल है, किसान परिवार के हैं और किसानों के लिए उनको दर्द है । हम मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि कपास का जो आपने रेट फिक्स कर दिया, उसका हम जबर करके स्वागत कर लेते हैं, लेकिन मंत्री जी के द्वारा हम टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से कहना चाहते हैं कि फाइनेंस या दूसरी मिनिस्ट्री से सूत का भाव कैसे फिक्स कराते हैं यह बताएं । जब मन चाहता है सेठ, साहूकार मनचाहे कपास के दाम वसूल लेते हैं। शर्म की बात है कि एन०टी० सी० की मिल 1300 करोड़ रुपए की घाटे में जा रही है और उसको 1300 करोड़ रुपए यह सरकार बराबर दे रही है । यह रुपया फालतू थोड़ा है, इस पर निगाह रखनी चाहिए । इन सारी मिलों को बेच देना चाहिए, बंद करना चाहिए और मुलाजमों के लिए कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए । तो मैं आपके जरिए से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे ऐलान करें कि कपास की पैदावार बढ़ाए और उसका ऐक्सपोर्ट भी करावाएं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है, वहां पहले जमाने में कपास पैदा होती थी, लेकिन आज नहीं होती । मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको फारेन ऐक्सचेंज कमाना है तो उत्तर प्रदेश में कपास की पैदावार के लिए आपको योजना चलानी चाहिए, चाहे आप 3 हजार रुपए फी एकड़ किसान को सबसिडी दे और दूसरे प्रान्तों के जो स्पेशलिस्ट हैं कपास पैदा कर सकते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में भेजें ।

दूसरी बात यह है कि रेशम हमको चाइना नहीं देगा । हमारा रेशम उद्योग खत्म होता जा रहा है, हिन्दुस्तान के अंदर रेशम का भाव 650 से 1250 रुपए फी किलो कर दिया गया है । अतः रेशम की पैदावार के लिए किसानों को 3000 रुपए की सबसिडी मिलनी चाहिए, किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे लोग आगे बढ़ सकें ।

मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या उत्तर प्रदेश में कपास पैदा करने के लिए, रेशम पैदा करने के लिए तीन-तीन हजार रुपये फी एकड़ किसानों को सबसिडी के रूप में देंगे ? क्या सूत का रेट फिक्स करायेंगे ? मंत्री जी अगर रूई की यहां कमी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी दानिशमंदी है कि लोग एलान करे काटन यार्न का एक्सपोर्ट करो, कपास यार्न को एक्सपोर्ट करो । यह एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि इसकी पैदावार न बढ़

जाये। आज कौन चाह रहा है कि एक्सपोर्ट हो? किसान को इसका लाभ नहीं मिलता। सेठ साहुकार और दिग्गज लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। रातों रात कपास का एक्सपोर्ट हो जाता है, कॉटन का एक्सपोर्ट हो जाता है जो लखपति है वह करोड़पति हो जाता है और जो करोड़पति है वह अरबपति हो जाता है। हम गरीब मजदूरों के, किसानों के पावरलूम, हैंडलूम बंद हो गये हैं। लोग भूखों मरने लगे हैं। जो हाथ से काम करते हैं वह भूखों रहने लगे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय भजन लाल जी ने जो कच्चे कपास और पटसन के मूल्यों के बारे में वक्तव्य दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे पूर्ववक्ता ने शेरो-शायरी से अपना वक्तव्य शुरू किया था और भजन लाल जी भी थोड़े रसिक आदमी हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आप भी शुरू कर दीजिए।

डा० रत्नाकर पांडेय: मैं भी उसी में जोड़ देता हूं:

मुस्कराहट अन्धेरे की कम ना हुई,
तो शमां जलाने से क्या फायदा।
जिसमें कोई अदा कोई फन ही नहीं,
जिसमें दिल जीतने की कशिश ही नहीं,
ऐसे साकी का हाथों में प्याला लिए,
बीच महफिल में आने से क्या फायदा।

मान्यवर, कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करने के लिए डब्ल्यू-5 को टी डी-5 में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे व्यापक रूप से बुराई हो। 280 रुपये प्रति क्विंटल के दाम बढ़ा कर 17.50 रुपये कर दिये हैं। इसी तरह से टी डी-5 और डब्ल्यू-5 किस्मों का मूल्य अन्तर कर दिया गया है, 12.50 रुपये की जगह पर 15 रुपये कर दिया है। कैप्सूलरीज और ओलिटोरियस पटसन के संगत मूल्य का अन्तर निकाल कर भाव नियत कर दिये है। डब्ल्यू-5 ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 250 रुपये प्रति क्विंटल था वह 265 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह तो पटसन के विषय में आपने वक्तव्य दिया है। वास्तव में जो मिडिल मैन हैं चाहे पटसन के हो या कपास के वे एक किस्म से कोढ़ का रूप धारण किये हुए है जैसे कि शरीर में कोढ़ हो जाता है और सारे शरीर को अछूत बना देता है। जो उत्पादन करने वाले किसान है उसको वास्तविक रेट नहीं मिल पाते हैं। बीच का मिडिलमैन अपना घर भर रहा है।

आज देश में कपास की और पटसन की जितनी मिलें बंद हैं चाहे सरकारी उपक्रम में हो या सरकारी उपक्रम के बाहर हों, प्राइवेट सेक्टर में हो या मिक्स्ड सेक्टर में हो आपने भी कई बार माननीय चेयरमैन की हैसियत से नहीं एक सदस्य के रूप में इस चीज को उठाया था, मुझे स्मरण है, इन मिलों को चालू कराने के लिए कृषि मंत्री जी कहेंगे कि हमारा उत्पादन से मतलब है उसमें अधिक से अधिक सुधार करेंगे। कपड़ा मंत्री जी कहेंगे कि हमारा मिलों से मतलब है। जो हमारे कामर्स मंत्री जी है वह कहेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट से मतलब है और फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और कहेंगे और

6 P.M. योजना मंत्री कुछ कहेंगे। मैं माननीय भजन लाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर उनको सच्चा दर्द है और श्री राजीव गांधी जी के सच्चे खैरख्वाह बनते हैं तो वे इन सब की मीटिंग बुलावें और ऐसा करें जैसा हमारे मीर्जा साहब ने यह कहा था कि किसान लाभान्वित हों। आज हमारे महाराष्ट्र में जो विरोधी दल के लोग हैं व लोग कपास उत्पादकों को लेकर आन्दोलन करते हैं और उससे हमारा कितना नुक्सान होता है इससे हमसे आप अधिक परिचित हैं। इसी तरह से मिल के मजदूरों को लेकर दत्ता सामन्त ने बहुत बड़ा न्यूसेंस बम्बई में

[डा० रत्नाकर पांडेय]

खड़ा किया था । यह सब हमारी सरकार की कमजोरी के कारण होता है । मंत्री महोदय के विभाग से संबंधित एक चीज में कहना चाहता हूं । कोआपरेटिव से सम्बद्ध है । मैं काशी का रहने वाला हूं । अभी हमारे भाई अमीन अंसारी जी ने रेशम की बात कही है । वहां रेशम और गलीचों के बारे में आज सबेरे भी मैंने सवाल उठाया था । आपने मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं इसको फिर उठाना चाहता हूं । कोआपरेटिव आपके पास है और वहां के बुनकरों की मांग पर मेरी संस्तुति पर पांच हजार टन रेशम आपने वहां के लिए दिया । आप इसको नोट करें । इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं, वहां के बुनकर सिद्ध कर सकते हैं । आप इसके लिए कमीशन बैठाइये। वहां पर जाली कोआपरेटिव के नाम पर एक व्यक्ति को दे दिया गया । उसने कई नामों से कोआपरेटिव बनाये और बुनकरों ने बाजार में अधिक भाव पर खरीदा । मैं बनारस के बुनकरों का दर्द कह रहा हूं । आप चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं । आपने बुनकरों के लिए इतना काम किया, लेकिन सत्ता के दलाल कोआपरेटिव के नाम पर उस को हड़प करके पांच हजार टन उड़ा ले गये । आप इसकी जांच कराइये और कमीशन बैठाये । इसको पूरे बनारस के बुनकर सिद्ध कर देंगे । आपके पास इसकी शिकायत भी हुई होगी । आप न चीजों को बंद कराइये, अगर आप राजीव गांधी के खैरख्वाह बनते हैं तो ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुदरती आपदाओं से जो फसलें नष्ट हो जाती हैं, चाहे जूट की हो या कपास की हों उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए । मुझे महाराष्ट्र में घूमने का पिछली बार मौका मिला था । वहां पर चीनी मिलों के जो कोआपरेटिव्ज हैं उनमें किसान अपना गन्ना लाद कर ले जाते हैं और स्वयं तोलते हैं । उनका उसमें शेयर होता है । यह किसानों की प्रोपर्टी होती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस प्रकार की कोई व्यवस्था करने जा रही है? कपास उद्योग में और पटसन उद्योग में जो उत्पादन करते हैं उनके बीच में कोई मिडिलमैन न होकर क्या राष्ट्रीय स्तर पर स्थान स्थान पर आप कोआपरेटिव बनाएंगे ताकि जो दलाल सब कुछ खा जाते हैं या जो बड़े आकर्षक लोग हैं वे माल को भेजकर विदेशी मुद्रा कमाने के नाम पर किसानों का शोषण करते हैं उन को रोकेंगे? गुजरात की अभी चर्चा हुई है । कुदरती आपदाओं के कारण वहां बड़ी कठिनाइयां पड़ा हुई थीं । पिछले चार साल तक वहां सूखा पड़ा । मुझे भी पोरबन्दर जाने का मौका मिला था । वहां पर ट्रकों से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा था । उत्पादन के लिए पानी की बात कौन करे । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कुदरती आपदाओं से जिन किसानों की फसल नष्ट हो जाती है क्या आप उनको ग्रांट देंगे ताकि उनके घरों में चूल्हे जल सकें ? सी०सी०आई०और जे०सी०आई० बहुत देर से बाजार में जूट और कपास आया है, मैं जानना चाहता हूं कि इन सेन्टर्स पर कितनी कपास आई हुई है? एक बहाना लिया जाता है कि दिस इज ए स्टेट सबजेक्ट, वी हेव नो बिजनैस टू दिस । आप पैसा देते हैं और आप मानिटरिंग नहीं करें कंट्रोल नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी यह बतायें कि कपास और जूट जो मार्केट में आ चुका है वह कितना और कब आया है? व्यापारी और बिचौलिये और सी०सी०आई०और जे०सी०आई० मिलकर जो धांधलियां करते हैं, सी०सी०आई० के लोग भी उसमें मिले होते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी एक्सपोर्ट संबंधी नीति भी है । उसमें क्या कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं? जूट और कपास से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हो उसके लिये अपना उत्पादन, अपने देश में जो खपत और मांग है उसके प्रतिकूल क्या आप विदेशों में भेजेंगे, यह मैं मंत्री महोदय से जानन चाहता हूं? धन्यवाद ।

श्री नरेश सी० पगलिया (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जूट और काटन की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है। हालांकि हम लोगों को उम्मीद थी तथा बंगाल और बिहार के किसान चाहते थे कि जूट में गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस ज्यादा दे। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश के किसान चाहते थे कि काटन में हमें सपोर्ट प्राइस ज्यादा मिले। लेकिन फूल नहीं फूल की पंखड़ी सही कुछ न कुछ बढ़ाया है। इसके लिये मैं कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्री श्री भजन लाल जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भजन लाल जी हरियाणा से आते हैं और कृषि के क्षेत्र में हरियाणा ने सारे देश में काफी क्रांति की है और यह उनका पेट सबजेक्ट है। उपसभाध्यक्ष जी, जिस स्टेट से आप आते हैं, महाराष्ट्र, दुर्भाग्य से वह पूरा काटन ग्रोइंग एरिया है। बहुत बड़ी मात्र में हिन्दुस्तान की अच्छी कपास हमारे एरिया में होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कपास का उत्पादन करने वाला किसान काफी परेशान है। जिस साल फसल ज्यादा होती है उस साल भाव नहीं मिलते और जिस साल फसल कम होती है उस साल भी भाव नहीं मिलते। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ने काटन मोनोपली स्कीम बनाई है जिसके अन्तर्गत किसानों को कुछ राहत मिलती है। लेकिन उसके जो प्राइस हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिस भाव से खरीदती है उसके भाव और आपके सी.सी.आई० के भाव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वहां प्राइवेट ट्रेडर्स जो खरीदते है उसमें डबल का फर्क होता है। महाराष्ट्र के साथ आंध्र का बार्डर है। इस बार्डर एरिया में 600 और 650 से अगर सरकार काटन का प्रोक्योरमेंट करती है तो प्राइवेट व्यापारी 600 की जगह पर 1000 और 1200 का रेट खोलते हैं। इस तरह 400 से 600 रुपये प्रति क्विंटल कपास के भावों में अंतर है। सी०सी०आई० और महाराष्ट्र सरकार की जो कोआपरेटिव से परचेंजिंग होती है उनके भावों को देखकर किसान को मजबूर होकर अपना कपास बार्डर उस पार ले जाता पड़ता है। उसमें उन्हें पुलिस वालों से तकलीफ होती है। उस कपास को वे व्यापारी दो-तीन महीने के उधार पर खरीद लेते हैं और उनको तीन-चार इंस्टालमेंट में पैस देते हैं। यही हालत दूसरी जगहों पर भी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इस विषय में भी सोचें कि बंगाल और बिहार के जो जूट उत्पादक किसान हैं उनकी हालत खराब है। जूट से जो भी चीजें बनती थी उसकी जगह अब पोलीथीन ने ले ली है। आज सीमेंट पोलीथीन के बैग में आता है, अनाज पोलीथीन के बैग में आने लगा है। इसी प्रकार से दूसरे आइटम्स हैं। पूरी जगह पोलीथीन बैग के लेने के कारण जूट के किसानों पर बड़ी मात्रा में असर हुआ है। इसके कारण जूट उत्पादक किसान जो बंगाल, बिहार और देश के अन्य इलाकों में हैं वे बहुत परेशान हैं। इसी तरह से काटन की जगह, जिससे हमारा सूती कपड़ा बनता था और जिसको देहातों के 80 प्रतिशत किसान पहनते थे, उसकी जगह आज पोलियेस्टर ने ले लिया है। इस प्रकार से उन पर भी इसका असर हुआ है। पिछले साल, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, आप और हम सब लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि हमारे यहां कपास का उत्पादन काफी हुआ है इसलिये मोनोपली प्रोक्योरमेंट स्कीम के अन्तर्गत, जो हमने लाखों गांठें कपास की बनाई हैं, उनको एक्सपोर्ट करने की परमीशन दी जाय। 300 से 400 लाख गांठें बाहर भेजनी आवश्यक हैं अदरवाइज हमारी स्कीम घाटे में आ जायेगी और किसानों को बोनस नहीं मिलेगा। इस प्रकार की वकालत हमें प्रधानमंत्री के सामने करनी पड़ी थी। उस साल कपास का उत्पादन ज्यादा हुआ था। लेकिन मार्केट में उचित मूल्य नहीं मिल रहा था और हमको उसे बाहर भेजना पड़ा था। इस साल कपास का उत्पादन कम है। मार्केट में सी०सी० आई० और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसमें उन्होंने किसानों को कम रेट दिया है और प्राइवेट व्यापारियों ने

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

ज्यादा दिया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपको कपास के विषय में सोचना होगा। हमारे जो हैंडलूम, पावरलूम और टैक्सटाइल मिले हैं, उनमें काम करने वाले कामकार है जो कि बहुत परेशान है। उनको समय पर सूत नहीं मिलता और अगर मिलता है तो ज्यादा कीमत पर मिलता है और अगर किसान अपनी कपास को मार्केट में बेचने आता है तो उसको कीमत नहीं मिलती। तो इस प्रकार से व्यापारी जो कपास खरीदते हैं वे लोग और जो लोग टैक्सटाइल मिलों के कामगार है। वे लोग इस प्रकार से जनता का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कपास और जूट के विषय में केन्द्रीय सरकार चाहे कामर्स मिनिस्टरी हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हों, चाहे कण्ड्रा मंत्रालय हो या एग्री-कल्चर मिनिस्टरी हो यह चारों मंत्रालय एक जगह बैठ कर के नेशनल लेवल पर एक पालिसी तय करें कि हमारे देश में जितनी कपास या जूट का निर्माण होता है उसकी खरीद कोआपरेटिव बेसिस पर होनी चाहिये कोआपरेटिव के माध्यम से होनी चाहिये और उससे बनने वाला धागा या अन्य चीजें भी कोआपरेटिव के माध्यम से बननी चाहियें। इससे टेक्सटाइल मिल्स को सूत उचित भाव में मिलेगा, किसानों को कपास की उचित कीमत मिलेगी और जूट उत्पादक किसान को भी उचित दाम मिलेंगे। इस प्रकार से जब तक केन्द्रीय सरकार नेशनल लेवल पर एक पालिसी तय नहीं करती है तब तक हमारे यहां किसान और मजदूर दुखी रहेगा। जो व्यापारी या बिचौलिये हैं उनको फायदा होता है और टेक्सटाइल मिलों के मालिकों का फायदा होता है उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बम्बई में जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मालिकों ने अपनी टेक्सटाइल मिलों को सिक मिल बता कर बन्द कर दिया है और बम्बई की उस जमीन को बेच कर बम्बई से बाहर या दूसरे राज्यों में अपनी मिलें ले जाना चाहते हैं जिससे डेढ़ लाख मजदूर बम्बई का, जिस बम्बई से आप भी आते हैं, आज बेकार हैं और वह अपने परिवार के लोगों के बारे में चिन्तित हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई केन्द्रीय सरकार की योजना है? आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भजन लाल: उपसभाध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों ने जो हमने सपोर्ट प्राइस घोषित किया है उसका समर्थन किया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं लेकिन कुछ सुझाव भी दिये गये हैं, कुछ खदशे भी जाहिर किये गये हैं। एक खदशा आपने भी जाहिर किया। उनके बारे में जरूर आपकी सेवा में निवेदन करूंगा और बताना चाहूंगा। सब से पहले नारायणसामी जी ने स्टेट ट्रेडिंग शब्द के बारे में कहा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने स्टेट ट्रेडिंग शब्द को निकाल दिया है। इस तरह की कोई शिकायत अब खरीददार में नहीं आएगी। यह वाकई एक समस्या थी इसको हमने दूर कर दिया है। जहां तक इन्होंने कहा पटसन और जूट के बारे में काटन की जरूरत ज्यादा है उत्पादन कम है और आपने भी एक बात कही थी कि जो टारगेट फिक्स करते हैं उत्पादन का या जितना उत्पादन होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। आप जानते है कि पिछले तीन चार साल से सूखा पड़ा उसकी वजह से उत्पादन मे थोड़ी कमी रही

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो आपका फाइनल इस्टीमेट है वह एक्चुअल से बहुत ज्यादा कम था 30 परसेंट कम था।

श्री भजन लाल: उत्पादन का इस्टीमेट कहा ना आपने ? मैं वही कह रहा हूं कि उत्पादन का इस्टीमेट इसलिए

कुछ कम हुआ लेकिन 30 परसेंट कम नहीं हुआ। कुछ कम हुआ वह सूखे की वजह से हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो काटन का उत्पादन हुआ था।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): भजन लाल जी, आप समझे नहीं हैं। आपने इस्टीमेट बताया 66 लाख बेल्स का और उत्पादन हुआ 90 लाख बेल्स का।

श्री भजन लाल: ज्यादा हुआ है। कम होने का सवाल नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): अगर आप कम बताएंगे तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे।

श्री भजन लाल: कम बताएंगे तो उसमें भाव बढ़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): एक्सपोर्ट पालिसी के लिए कितना उत्पादन होगा (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल: आप ठीक कहते हैं कि पिछले साल भी हमारा जो उत्पादन है वह तकरीबन 85 लाख गांठ का हुआ है और इस दफा हमारा उत्पादन 95 से 100 लाख गांठ के बीच में होगा। इस दफा उत्पादन बढ़ा है घटने का कोई सवाल नहीं है। हमारे देश में जो लागत है वह कुल 90 लाख गांठ की है। इस दफा हमारे पास पांच सात लाख या दस लाख गांठ फालतू हो सकती है। जो हमारे पास फालतू होंगी वह हम कोशिश करेंगे कि दूसरे देशों को बाहर भेजें ताकि भाव टिका रहे काटन का भाव मंदा नहीं जाए और किसानों को सही कीमत मिल सके। जहां तक काटन को बाहर से मंगाने का ताल्लुक है पिछले साल हमने एक लाख गांठें बाहर से मंगवाई। पहले कहा गया कि 10 लाख गांठ लें लेकिन हमने कहा कि इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर 5 लाख का फैसला हुआ लेकिन आई सिर्फ एक लाख गांठें। इस दफा बाहर से मंगाने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि कुछ देशों के साथ एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जिनके नीचे कुछ चीजें मंगानी पड़ती हैं। लेकिन इस बार हमारी कोशिश यही होगी कि एग्रीमेंट के नीचे और कोई चीजें मंगायें लेकिन काटन बाहर से न मंगाये। बल्कि हम बाहर भेजने की कोशिश करेंगे।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग: मेरा कहना यह कि आज अगर . . .

श्री भजन लाल: मैं आपकी बातों पर भी बारी से आऊंगा। आप सुनने की कृपा करिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आपका भी जवाब देंगे।

श्री मीर्जा इर्शाद बेग: मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए, अभी निर्यात नहीं हुआ है जब कि आप ने कहा है कि एक्सेस है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अभी तक हमने निर्णय नहीं लिया है और किसानों की जो कपास है वह बाहर पहुंच चुकी है। उनके घर में आज रुई की एक फूटी भी नहीं है। लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि हम सीजन आने के पहले उसके लक्ष्यांक तय कर दें। उसी वक्त क्यों एक्सपोर्ट की नीति घोषित करते हैं। आप करवायेंगे इसको मान्यवर, आप करा सकते हैं।

श्री भजन लाल: आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा अन्तर तो नहीं है। जितनी जरूरत है उससे थोड़ा अन्तर है। अगर हम पहले घोषित कर दें कि हम बाहर भेजेंगे तो जो बुनकर हैं उनके सामने, गरीब लोगों के सामने दिक्कत आ जाएगी जिनको लेना होता है, उसके भाव और बढ़ जायेंगे दूसरा, पहले पूरा अन्दाज नहीं होता है कि वाकई इतनी पैदावार होगी या नहीं होगी जब कुछ आधे ज्यादा से माल मारकेट में आ जाता है तब जाकर अंदाज लगता है। इसके अलावा, आप जानते हैं कि काटन जब खेत में से लेते हैं तो उसको एक साथ नहीं काटते हैं, कम से कम तीन बार

[श्री भजन लाल]

काटन खेत में से चुगना पड़ता है और देशी को तो चार-पांच दफा चुगना पड़ता है । अलग-अलग क्वालिटीज हैं देशों है, निरमा है, एच–14 है, 447 है, 444 है । अलग अलग क्वालिटीज हैं लेकिन बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी को भी तीन बार चुगेंगे । एक पौधा तीन बार फल देता है । तीन बार कपास निकालनी पड़ती है । दो दफा निकाल लेते हैं तब जाकर पता चलता है कि इतनी यील्ड इस एकड़ में, इस हैक्टेयर में होने वाली है । इसलिए पहले इसका पूरा अन्दाज नहीं लगता है । इसलिए कई दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी एरिया से अन्दाज हो जाता है । एरिया घटा नहीं है, एरिया भी हमारा कुछ बढ़ा है चूंकि बरसात बहुत अच्छी थी, फसल का झाड़ अच्छा रहा । लेकिन कई दफा एरिया ज्यादा हो जाता है और सूखा पड़ जाये तो यील्ड कम होगी उत्पादन कम हो जाएगा । ये दिक्कतें आती हैं । लेकिन फिर भी हम सारी बातों को देखकर जो ठीक बात होगी वह करेंगे ताकि किसानों को मुनासिब भाव मिले । लेकिन साथ में बुनकरों का भी ध्यान रखना पड़ता है । कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है । जहां तक सेंटर खोले जाने का सवाल है...

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : मंत्री जी, मैं एक मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा ।

श्री भजन लाल : मैं आपकी बात पर भी आऊंगा ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : एक बात यह है कि 3–4 साल से कन्टीन्युअस हमारा बेल्स बढ़ा दिया गया है । तो इसको मद्देनजर रखते हुये अगर कोई पालिसी बना सकते हैं तो वह उचित रहेगा । ऐसा मुझे लगता है क्योंकि बुनकरों का कोटा तो फिक्स रहता है ।

श्री भजन लाल : रामसिंह जी ने कहा कि सेंटर ज्यादा खोलने चाहियें । आप जानते हैं कि सी. सी. आई. काटन को परचज करती है और जूट को जूट की संस्था करती है । लेकिन हमारी कोशिश यह होगी कि सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा खोले जायें । अब जो उत्पादन का प्राक्योरमेंट है उसका 20 प्रतिशत ही मुश्किल से प्राक्योर करते हैं बाकी सब प्राइवेट लोग करते हैं, प्राइवेट मिल वाले करते हैं चाहे वह जूट हो या काटन । जूट का आप जानते हैं कि जूट के बोरे बनाने वाली बहुत सी प्राइवेट फैक्टरीज हैं, वे लेती हैं और मिलें लेती हैं, कपास को कपड़ा बनाने वाले, धागा बनाने वाले प्राइवेट मिल वाले लेते हैं । लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स खोले जायें ताकि लोगों को मुनासिब कीमत मिलती रहे, उनको तकलीफ न हो ।

जाधवजी ने कहा कि महाराष्ट्र में काटन मोनोपोली स्कीम जो है उसकी मियाद बढ़ाई जाये । आप जानते हैं 10 साल उसकी मियाद रखी थी । उनका कोई केस अभी तक हमारे पास नहीं आया है ज्योंहि हमारे पास आयेगा तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे ।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : हम आपकी मदद चाहते हैं ।

श्री भजन लाल : एक आपने जो बात कही कि कृषि को उद्योग करना चाहिए । अगर हम कृषि को उद्योग मान लेंगे तो किसानों को बड़ी भारी तकलीफ हो जायेगी । आप जानते हैं कि जब उद्योग मान लेते हैं तो बाकायदा उसका रिटर्न भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स वगैरह सब हो जाएगा और फिर जो हम सब्सीडाइज्ड करते है, जितनी सब्सिडी हम देते हैं, खाद पर बीज पर, इरीगेशन पर, इनसे वे वंचित रह जायेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बेफिक्र रहिये उन पर इन्कम टैक्स नहीं रहेगा ।

श्री भजन लाल : कैसे नहीं लगेगा ? यदि आप उसे इंडस्ट्री घोषित कर देंगे, तो उस पर हर हालत में इनकमटैक्स उसे देना पड़ेगा ।

श्री विट्ठलराव माधव राव जाधव : अगर आप प्राइसेज बढ़ा देंगे तो लोगों को इनकम-टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री भजन लाल : जहां तक प्राइसेज की बात है, यदि कृषि को आप उद्योग घोषित कर देंगे, तो इनकम-टैक्स से वह कैसे बच सकेंगे ? . . (व्यवधान) वह अधपढ़ा किसान है,वह कैसे हिसाब और अकाउन्ट्स रख सकेगा ।

श्री मीर्जा ईर्शाद बेग : इसके लिए प्रावधान कर दीजिए कि वह एक्जेम्प्ट है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : वह हो सकता है कि एग्रीकल्चर के लिए इनकम-टैक्स में हो . . . (व्यवधान) वह हो सकता है ।

श्री भजन लाल : एक इन्डस्ट्री से आप टैक्स लें और एक को छोड़ दें, तो यह कैसे हो सकता है ? इस पर विचार करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है ।

फिर, श्री बागड़ोदिया जी ने कहा कि कपास के भाव को बढ़ाना चाहिए था । आप जानते हैं कि जब भाव तय करते हैं, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर करते हैं और जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को मुबारकबाद दी, यह सही बात है । आप जानते हैं कि बुआई से पहले इतनी जल्दी भाव बहुत मुश्किल से तय हो पाता है । पिछले दो सालों में लगातार फसल बोने से पहले--क्योंकि अब काटन की बुआई का सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले किसान को बताया कि हम आगे आपको यह भाव देने वाले हैं ताकि किसान इस चीज को बो सके या जो जिन्स किसानों को फायदेमंद लगती है, वह बो सकें और कितना अच्छा भाव दिया है । पिछले साल भी हमने 40–50 रुपए क्विंटल काटन के और 15–15 रुपए जूट के बढ़ाये हैं । इस बार भी हमने 40–50 काटन के और 17.50 रुपए जूट के बढ़ाये हैं । इसके पहले एक साथ इतने भाव हमने कभी नहीं बढ़ाये । यह इसलिए बढ़ाये हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य दे सकें और देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किसान कर सकें ताकि बाहर से हमें निर्यात नहीं करना पड़े, हमारे देश की मुद्रा बाहर न जाए, बल्कि बाहर बेचने के लायक हो सकें, इसके लिए यह भाव तय किए हैं ।

हम सारी बातों को देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट तथा रिलीज करने के बारे में भी सिस्टैमैटिक तरीके से काम हो, ताकि मार्केट में स्लम्प न आये ।

फिर मीर्जा ईर्शाद बेग साहब ने कहा कि कपास को बीमारी लग जाती है और इसके लिए एक नीति बनाई जानी चाहिये कि जहां बीमारी लग गई, वहां 20 प्रतिशत उन किसानों को भाव ज्यादा मिले ।

यह ठीक बात है कि गुजरात और आंध्र प्रदेश में पिछले साल कुछ बीमारी से फसल खराब हुई उसके लिए इस बार हमने पूरी कोशिश की है कि बीमारी न लगे । बल्कि आंध्र प्रदेश ने हमें लिखा था हमें बाहर विदेशों से दवाई मंगाने की इजाजत दी जाए । हमने उनको इजाजत भी दी और कुछ दवा आई भी है, ताकि किसी तरह से बीमारी किसान की फसल को नहीं लगे और उसकी पूरी रोकथाम की जाये । इसके बारे में हम पूरी तरह से कोशिश में हैं ।

माननीय विकल साहब ने कहा कि कमीशन ने क्या सिफारिश की थी और सरकार ने क्या भाव तय किये हैं ? पिछले साल कमीशन ने बल्कि कुछ कम रिकमेंड किया था, हमने उससे फालतू दिया । इस बार जो कमीशन ने रिकमेंड किया है, वही भाव हमने दिया है ।

श्री राम चन्द्र विकल : क्यों दिया है वही बात तो हम जानना चाहते हैं ?

श्री भजन लाल : मैंने कहा न कि जो मैंने अभी अनाउंस किया है--650 रुपये और 540 रुपए । पांच सौ वालों का

[श्री भजन लाल]

540 रुपए रिकमेंड किया है और 600 वालों का 650 रुपए रिकमेंड किया था । हमने वही दिया जो कमीशन ने रिकमेंड किया है, जिसको मैंने अभी अनाउंस किया है ।

कई माननीय सदस्य : धन्यवाद ।

श्री भजन लाल : आपने कहा कि लागत कुछ ज्यादा आती है और भाव कम हैं। तो आप जानते हैं कि एक-एक बात का हिसाब लगाकर किसान को लाभकारी मूल्य देने की कोशिश की है ।

इसके साथ ही विकल साहब ने एक बात कही है कि कुछ जमीन में कपास होती नहीं है । उपसभाध्यक्ष जी, विकल साहब भी बहुत अच्छे जमींदार है और मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया है । आप जानते हैं कि विकल साहब, कि कुछ एरिया जिसमें बहुत ज्यादा खाद डालना शुरू कर दें, पहले वहां चना पैदा होता था, पर खाद देने के बाद वहां चना नहीं हो सकता क्योंकि चना खुद खाद है । चने और खाद का मेल नहीं है । जिस जमीन में खाद डल गई, उसमें चना नहीं होता ।

बरानी एरिया में जाकर देखें, जहां बरानी एरिया में खाद नहीं डलती है, वहां आज चना होता है ।

इसी तरह से कपास भी बहुत से एरिया में नहीं होती । पहले पंजाब में मुक्तसर और लुधियाना में बहुत ज्यादा कपास पैदा होती थी, पर आज उस एरिया में कपास नहीं होती है । आज पंजाब में कपास कहां होती है, मुक्तसर और फिरोजपुर जिले में कपास ज्यादा होती है, बाकी एरिया में कम होती है । आज हरियाणा पंजाब के मुकाबले में बराबर कपास पर आ गया है । पहले पंजाब के मुकाबले में हरियाणा में आधी कपास भी पैदा नहीं होती थी, लेकिन आज काफी अच्छी होती है । इसी तरह से कुछ एरियाज में, जमीन में कुछ ऐसी चीज हमने डालनी शुरू कर दी जिस की वजह से काटन उस एरिया में कम होती है । इसलिए आप जानते हैं कि कुछ चीजें बोने की वजह से जमीन के अन्दर भी फर्क आ गया है । उसकी वजह से काटन कम होने लगी है और चना भी कम हो गया है । नए एरिया में कपास और चना बल्कि ज्यादा उपज देने लग गया है । इसी तरह से अंसारी साहब ने कपास के बारे में कहा है कि कुछ लोगों ने छिपा रखी है, उसे बाहर निकलवाना चाहिए । आप जानते हैं कि कपास छुप नहीं सकती । जब भाव का मसला आता है, तेजी और मंदी को दुनियां में कोई रोक नहीं सकता और फिर हमने सारे देश में कोई बैन नहीं लगा रखा है । सारे देश में कपास, पटसन जहां-जहां कोई ले जाना चाहे वहां-वहां वह ले जा सकता है और जहां से कोई लाना चाहे वहां से वह ला सकता है । उसके ऊपर कोई बैन नहीं है ताकि मिल वालों को भी, बुनकरों को भी, पावरलूम वालों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो । एक बात आपने ठीक कही कि मिलों को घाटा जो होता है, मिलें जो घाटे में चलती हैं । कुछ मिलें सिक पड़ी हुई हैं उनको चलाना चाहिये । कुछ महकमें अलग-अलग हैं । एक महकमा कहता है कि मेरे अंडर नहीं है, मैं कहता हूं कि मेरे अंडर नहीं है एग्रीकल्चर का काम है, यह ठीक बात है और आप जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी सांझी होती है। सरकार का कोई भी अदारा हो या कोई भी संस्था हो, उसमें जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जो सैंटर में मंत्री बैठे हुये हैं उन सबका यही कर्तव्य बनता है कि सारा सिलसिला ठीक से चले । उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सिक मिलों को हम चालू करें और जो घाटा है वह कम करें और घाटा नहीं हो । जहां तक रेशम का सवाल है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के बारे में इसमें जो भी आपने सुझाव दिए हैं इनपर जरूर हम विचार करेंगे ।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : मैं यह कह रहा था कि हमारे सूत का भी रेट फिक्स करवा दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह उसके हाथ में नहीं है ।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : यह आपके जिम्मे है ।

श्री भजन लाल : मैंने यह नहीं कहा कि यह मेरा नहीं है, मैंने यही कहा कि कैबिनेट में जो मंत्री बैठ हैं उन सबकी साझी जिम्मेदारी है । प्रधान मंत्री जी खुद चाहते है कि इस मामले में किस तरह से यह सारा मामला ठीक चले । रत्नाकर पाण्डय साहब ने कहा कि मिलें बन्द पड़ी हुई हैं उनको चलाना चाहिये । यह ठीक बात है और उसके लिए सबकी एक मीटिंग बुलानी चाहिये । उन्होंने ठीक कहा है कि जब तक चार-पांच मिनिस्ट्रीज बैठ करके एक मीटिंग करके इसका हल नहीं निकालेंगी तब तक यह बात ठीक नहीं रहेगी कि एक उन्होंने जाली कोआपरेटिव सोसायटी का नाम लिया कि रेशम अलाट करवा लिया और बाकायदा ब्लैक में यह बच गये हैं इन्होंने अभी नोटिस में लाया है, इसकी बाकायदा हम इन्क्वायरी करवायेंगे और दोषी व्यक्ति के खिलाफ बाकायदा कार्यवाही की जायेगी । इसी तरह से सी.सी.आई. के बारे में कहा कि कुछ धांधली है तो इसको भी हम देखेंगे कि क्या धांधली है । एक पुरुलिया साहब ने कहा है कि मोनोपोली और प्राइवेट व्यापारी कोआपरेटिव वाले में अन्तर है इसको बाकायदा कोआपरेटिव के नीचे ही सब को लेना चाहिये और जूट की जगह पोलिथीन ने ले ली, नेशनल लेवल पर एक पालिसी बनानी चाहिए, यह ठीक बात है । जूट के सिलसिले में ठीक रहना चाहिए लेकिन पोलिथीन के बारे में आप जानते हैं कि उसमें बहुत सी लेबर, बहुत से वर्कर्ज काम में लगे हुये हैं अगर उसको बन्द कर दें तो सारे वर्कर्ज बेकार हो जायेंगे । बहुत सी बातें देख करके बाद में निर्णय लिए जाते हैं । इसलिए आज का फैसला भाव का है । सारी बातें किसानों के हित में और गरीब आदमियों के हित में, दोनों को ध्यान में रख कर बाद में सरकार भाव तय करती है ताकि सब का हित सामने रहे और किसी भी तरह से किसी के दिल और दिमाग मे कोई ज्यादती अन्याय की भावना या किसी को भी कोई तकलीफ न हो । इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही सरकार भाव तय करती है । बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House now stands adjourned and will again meet tomorrow, the 17th March at 11 A.M.

The House then adjourned at thirty-minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 17th March 1989.